रंजन गोगोई के आने से राज्यसभा में गर्मी बढ़ने के संकेत

माला दीक्षित, नई दिल्ली

पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के राज्यसभा में मनोनयन और शपथ ग्रहण के वक्त हुआ विवाद अभी थमने वाला नहीं है। अब गोगोई की ओर से पलटवार होने वाला है और उससे राजनीति गरमाने वाली है। मीडिया से बातचीत में पूर्व सीजीआइ ने साफ संकेत दे दिया है कि उन पर सवाल उठाने वाले न्यायाधीशों और राजनीतिज्ञों को भी कई जवाब देने होंगे।

राज्यसभा सदस्य मनोनीत होने के बाद जब गोगोई ने सदस्यता की शपथ ली तो विरोध में नारे लगाने के साथ-साथ कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्षी सदस्य सदन से वाकआउट कर गए थे। उस समय पूर्व सीजेआइ सिर्फ इतना कहकर चुप हो गए कि वह बताएंगे कि सदस्यता क्यों स्वीकार की, लेकिन अब परत दिखने लगी है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और जानेमाने वकील कपिल सिब्बल ने पूर्व सीजेआइ को इंगित कर अपने ट्वीटर हैंडल पर पांच सवाल पूछे थे। सवाल थे कि क्यों आपने अपने ही केस की सुनवाई की, इशारा यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई की ओर था। दूसरा प्रश्न- राफेल मामले में सीलबंद लिफाफे में दस्तावेज स्वीकारने से संबंधित था। अन्य इलेक्टोरल बांड का मुद्दा, राफेल मामले में सरकार को क्लीन चिट देने और सीबीआइ निदेशक को हटाने के मामले से संबंधित थे। पूर्व सीजेआइ ने चैनलों से बातचीत में सिब्बल के सवालों का जवाब दिया। सिब्बल और गोगोई दोनों राज्यसभा सदस्य हैं।

मीडिया को दिए साक्षात्कार में गोगोई के जवाब और तेवर इसी ओर इशारा करते हैं

रंजन गोगोई फाइल फोटो

एक चैनल में गोगोई ने कपिल सिब्बल पर आरोप लगाते हुए चौंकाने वाला तथ्य उजागर किया और यहां तक कह दिया कि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के कार्य आवंटन पर सवाल उठाने वाली सुप्रीम कोर्ट के चार जजों की ऐतिहासिक प्रेस कांफ्रेंस, जिसमें वह खुद भी शामिल थे, के बाद सिब्बल जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग पर मेरा समर्थन चाहते थे और इसके लिए मेरे घर आना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें अपने घर नहीं आने दिया।

पूर्व सीजेआइ ने उनकी नियुक्ति पर सवाल उठा रहे पूर्व न्यायाधीशों पर भी निशाना साधा। एक पूर्व जस्टिस के बारे में तो यहां तक कहा कि तीन वजहें थीं जिसकी वजह से उन्हें सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत नहीं किया गया और उन तीन में से एक वजह करोड़ों रुपये की संपत्ति के सौदे से भी जुड़ा मामला भी था जो 2008 में सुप्रीम कोर्ट आया था। गोगोई ने कहा कि ये मैटर रिकार्ड में है और आरटीआइ डाल कर उसके बारे में जाना जा सकता है।

राम जन्मभूमि केस की लगातार लंबी सुनवाई कर अपने कार्यकाल में जल्दी निपटारा करने के आरोपों पर पूर्व सीजेआइ ने कहा कि अगर किसी मामले की जल्दी सुनवाई नहीं की जाती तो उसकी आलोचना होती है और अगर जल्दी सुनवाई कर निपटाया जाता है तो उसकी भी आलोचना होती है। आखिर चीफ जस्टिस क्या करे। लंबे समय से मामला लंबित था उसे निपटाया जाना चाहिए था। वह फैसला उनका अकेले का नहीं था, पांच न्यायाधीशों का सर्वसम्मति का फैसला था।

राफेल फैसला भी तीन न्यायाधीशों का था। राफेल मामले में सील बंद लिफाफे के दस्तावेज स्वीकार किए जाने के बारे में पूर्व सीजेआइ ने कहा कि सील बंद लिफाफे की प्रक्रिया टूजी मामले में भी अपनाई गई थी और अभी हाल में शाहीन बाग मामले में भी वकील संजय हेगड़े ने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में जमा की है जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया है, उस पर सिब्बल ने सवाल नहीं उठाए। पूर्व सीजेआइ ने कहा कि राफेल मामले में सील कवर में राफेल की कीमत तथा एयरक्राफ्ट पर लगे उपकरणों की कीमत आदि थी। स्पष्ट है कि जब गोगोई संसद में बोलेंगे तो कई परतें खुल सकती हैं।

सीआरपीएफ को मिले आधुनिक सर्विलांस उपकरण

नई दिल्ली, प्रेट्र : हाल में आकाश से नजर रखने के मिले आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल से सीआरपीएफ अब जंगल में छिपे नक्सलियों के और करीब पहुंच पाएगी और उन पर कार्रवाई कर सकेगी। यह बात सीआरपीएफ (केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल) के प्रमुख एपी माहेश्वरी ने कही है।

सीआरपीएफ के महानिदेशक ने बताया कि बल को हाल ही में अत्याधुनिक मानवरहित विमान और ऊष्मा से उपस्थिति जानने वाले उपकरण मिले हैं। इन उपकरणों और अपनी खुफिया टीम की मदद से बल अब नक्सलियों के और करीब तक पहुंच पाएगा-उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाएगा। इसके लिए जल्द बेहतर तालमेल वाली रणनीति बनाई जाएगी और उस पर कार्य होगा। इससे निकट भविष्य में वामपंथी चरमपंथ को खत्म करने में मदद मिलेगी। इस तरह के

कार्रवाई के लिए नक्सलियों तक बढ़ेगी सीआरपीएफ की पहुंच

खुफिया उपकरण जमीन पर कार्य करने वाले बलों के लिए बहुत मददगार होते हैं। इनसे सुरक्षा बलों को होने वाला नुकसान बहुत कम हो जाता है और सटीक कार्रवाई की संभावना बढ़ जाती है। बिना विलंब के मिलने वाली सूचना से सुरक्षा बलों को अपनी रणनीति में बदलाव और कार्रवाई या बचाव का मौका मिल जाता है। इससे अब छत्तीसगढ़ जैसे नक्सलियों के मजबूत गढ़ में सुरक्षा बल को खासतौर पर बहुत मदद मिलेगी। माहेश्वरी ने बताया कि सीआरपीएफ और अन्य एजेंसियों ने जिस तरह से नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों का निर्माण किया है, उससे यह सोच खत्म हो गई है कि सुरक्षा बल नक्सलियों के इलाके में नहीं पहुंच सकते हैं। अब उन्हीं का फायदा उठाकर कार्रवाई होगी।

अर्धसैनिक बलों के आवागमन पर पांच अप्रैल तक लगी पाबंदी

मुस्तैदी ▶ पांच को हालात की समीक्षा के बाद होगा आगे का फैसला

छुट्टियों पर चल रहे जवानों को अवकाश बढ़ाने की हिदायत

नई दिल्ली, प्रेट्र: अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों के आवागमन, नई जगह तैनाती, छुट्टी पर जाने अथवा रोजमर्रा के कामों पर पांच अप्रैल तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। रविवार को यह जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि कार्मिकों को जो जहां हैं उसको वहीं रहने की हिदायत दी गई है।

इसके साथ ही सभी जवानों व अधिकारियों से एक फार्म भरकर इस बात की तस्दीक करने को कहा गया है कि उनके परिवार के किसी सदस्य ने हाल के दिनों में विदेश यात्रा तो नहीं की। यदि ऐसा है तो उन्हें यह भी बताना होगा कि वे निर्धारित अवधि तक आइसोलेशन में रहे कि नहीं।

उक्त अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा बल (आइटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल(एसएसबी) व नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) को यह निर्देश जारी किये गये हैं। इन बलों में कार्मिकों की संख्या दस लाख से अधिक है। निर्देश जारी करने के पीछे मंशा यह है कि देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाले इन बलों को इस घातक बीमारी से कोई समस्या न हो। ये बल देश की व्यवस्था की रीढ़ हैं। इन्हें देश की सीमा और देश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का अहम जिम्मा मिला हुआ है।

रविवार को असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से मास्क पहने हुए बाहर निकलता भारतीय सेना का एक जवान। कोरोना वायरस को लेकर भारतीय सेना भी अलर्ट है। सेना सभी तरह के युद्धाभ्यासों पर पहले ही रोक लगा चुकी है। एएनआइ

इन बलों के जवान कैंपों में बहुत सटकर रहते हैं। अगर कोई एक जवान भी बीमारी की चपेट में आ जाता है तो संक्रमण को बड़े पैमाने पर फैलने से नहीं रोका जा सकता। इसी कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी बलों से पांच अप्रैल तक हर तरह के आवागमन पर पाबंदी लगाने को कहा है। पांच अप्रैल को फैसले की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद फिर कोई निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन सुरक्षाबलों के जवानों के सभी तरह के गैरजरूरी छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से रद कर दिया है।

उधर हवाई अड्डों की सुरक्षा करने वाले वल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने शनिवार को छुट्टी पर चल रहे अपने उन कार्मिकों से अवकाश बढ़ाने को कहा है जिनकी छुट्टियां पांच अप्रैल से पहले समाप्त हो रहीं हैं। इसके लिए उन्हें अपने वरिष्ठों को फोन से सूचना देने को कहा गया है। इसी तरह बीएसएफ ने भी दो दिन पहले पांच अप्रैल तक अपने कार्मिकों के सभी तरह के आवागमन पर पाबंदी लगा दी है। बल ने इस आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने को कहा है।

एनपीआर और जनगणना का पहला चरण टलने की संभावना

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना वायरस के प्रसार के मद्देनजर एक अप्रैल से शुरू होने वाली राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने और जनगणना-2021 के पहले चरण की कवायद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने की संभावना है। इस संबंध में औपचारिक आदेश एक-दो दिनों में जारी किया जा सकता है।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, इस मामले में सरकार में सर्वोच्च स्तर पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक एनपीआर को अपडेट करने और जनगणना के लिए घरों को सूचीबद्ध करने की कवायद एक अप्रैल से 30 सितंबर तक की जानी है।

पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय ने कहा था कि जनगणना-2021 और एनपीआर को अपडेट करने की तैयारियां चरम पर हैं और ये कवायद एक अप्रैल से शुरू होंगी। मालूम हो कि कई राज्य सरकारें एनपीआर का विरोध कर रही हैं और कुछ विधानसभाओं ने इस पर आपत्तियां जताते हुए प्रस्ताव भी पारित किए थे। जो राज्य एनपीआर का विरोध कर रहे हैं उनमें केरल, बंगाल, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार शामिल हैं। हालांकि ज्यादातर राज्यों ने यह भी कहा था कि वे जनगणना के लिए घरों को सूचीबद्ध करने की कवायद में सहयोग करेंगे।

सूचना साझा करने को दक्षेस आपदा प्रबंधन केंद्र ने लांच की वेबसाइट

नई दिल्ली, प्रेट्र : दक्षेस आपदा प्रबंधन केंद्र ने क्षेत्र में कोरोना वायरस से संबंधित सूचना को साझा करने के लिए एक वेबसाइट लांच की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ अपने हालिया वीडियो कांफ्रेंस में इसका प्रस्ताव दिया था। वेबसाइट में सदस्य देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या बताई गई है जो लगातार अपडेट हो रही है। इसका मकसद सदस्य देशों के बीच कोरोना से जुड़ी अपनी-अपनी जानकारी साझा करना है।

प्रतीकात्मक फोटो

वेबसाइट के अनुसार, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) के सदस्य देशों में अब तक 960 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 495 मामले पाकिस्तान में सामने आए हैं, जबकि भारत में 324, श्रीलंका में 77, अफगानिस्तान में 24, बांग्लादेश में 24, मालदीव में 13, भूटान में दो व नेपाल में एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस के कारण भारत में पांच, पाकिस्तान में तीन व बांग्लादेश में दो की मौत हो चुकी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने भी ट्वीट करके रविवार को इसकी जानकारी दी।

दक्षेस के सदस्य देशों के बीच वीडियो कांफ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से 10 मिलियन डॉलर (करीब 75 करोड़ रुपये) के आपात कोष का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा था कि कोरोना की इस महामारी से निजात पाने के लिए शोध की दिशा में दक्षिण एशियाई देशों के बीच साझा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) इसका समन्वय कर सकता है। इसके लिए सभी की सहमति की जरूरी है। उम्मीद है कि इस पर सभी देश जल्द आगे आएंगे।

वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भूटान के प्रधानमंत्री लोताय शेरिंग, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मुहम्मद सोलिह, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के विशेष सहयोगी जफर मिर्जा शामिल रहे।

बांग्लादेश दक्षेस आपात कोष को देगा 11.3 करोड़ रुपये

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश ने दक्षिण एशिया में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए दक्षेस कोरोना आपात कोष में 1.5 मिलियन डॉलर (करीब 11.34 करोड़ रुपये) के योगदान का एलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत दिनों इस आपात कोष की स्थापना का प्रस्ताव करते हुए भारत की तरफ से प्रारंभिक तौर पर 10 मिलियन डॉलर (करीब 75 करोड़ रुपये) की मदद की पेशकश की थी।

बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने बताया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दक्षेस सचिव के पक्ष में राशि का अनुमोदन कर दिया है। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन (दक्षेस) सचिव से बात हुई है। राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी

भारत 10 मिलियन डॉलर देने का कर चुका है एलान

है और इसके बारे में भारत को बता दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत के बाद आपात कोष में नेपाल और अफगानिस्तान एक-एक मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 7.56 करोड़ रुपये) के योगदान का एलान कर चुके हैं। मालदीव ने दो लाख व भूटान ने एक लाख डॉलर देने की बात कही है।

उधर, बांग्लादेश की एक हाई कोर्ट पीठ ने रविवार को प्राधिकारों को उचित मात्रा में लोगों की सुरक्षा वाले उपकरण की खरीद का निर्देश दिया। साथ ही कहा है कि इन उपकरणों की सभी अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स और कर्मचारियों तक आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए।

आज से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो सकती है संसद की कार्यवाही

नई दिल्ली, आइएएनएस : मोदी सरकार सोमवार से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। कई राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील का खुद ही पालन नहीं करने की आलोचनाओं को देखते हुए सरकार यह कदम उठा सकती है।

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार को दोपहर बाद दो बजे शुरू होगी। सरकार इस दौरान वित्त विधेयक पारित करा सकती है। सत्ता पक्ष सदन का इस्तेमाल लोगों से घरों में बने रहने की अपील करने के लिए भी कर सकता है। सूत्रों ने कहा कि सरकार इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक स्थगित करा सकती है। ऐसे समय में जब सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से जनता कर्फ्यू को संभव बनाया है तब सदन की कार्यवाही संचालित होने के कारण सरकार आलोचना का शिकार हो रही है। भाजपा के सदस्य दुष्यंत सिंह के करीब जाने के कारण तृणमूल कांग्रेस के डोरेक ओ ब्रायन और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जैसे कई सदस्य सेल्फ-क्वारंटाइन में चले गए हैं। भाजपा नेता दुष्यंत कोरोना वायरस से संक्रमित गायिका कनिका कपूर के संपर्क में आए थे और उसके बाद उन्होंने संसद की कार्यवाही में भाग भी लिया था। अब तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को अधिकृत रूप से पत्र लिखकर कहा है कि जानलेवा बीमारी का संक्रमण बढ़ने के कारण उसके सदस्य संसद में भाग नहीं ले सकते हैं।

सांसद विकास निधि का जरूरतमंदों की जांच कराने में हो इस्तेमाल

हैदराबाद, एएनआइ : एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सांसद विकास निधि का इस्तेमाल जरूरतमंदों की कोरोना वायरस जांच पर आने वाले खर्च का भुगतान करने में इस्तेमाल करने की इजाजत देने का प्रस्ताव किया है। ओवैसी लोकसभा में हैदराबाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्र ने शनिवार को कोविड-19 की जांच के लिए निजी लैब का भी दरवाजा खोल दिया। इसके बाद ही ओवैसी ने यह प्रस्ताव किया है। सरकार ने इसकी जांच का खर्च 4500 रुपये निर्धारित किया है। अभी तक सरकारी प्रयोगशालाएं ही जांच कर रही हैं और यह जांच मुफ्त है। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को टैग करते हुए ओवैसी ने कहा है, 'इस संकट का प्रसार रोकने के लिए हमें जांच बढ़ाने की जरूरत है। प्रह्लाद जोशी और ओम बिरला से आग्रह है कि सांसदों को, जो रोगी भुगतान नहीं कर सकते उनकी जांच पर आने वाला खर्च सांसद विकास निधि से भुगतान करने की अनुमति दें।'

आभार जताने के लिए आइएमए ने प्रधानमंत्री मोदी को सराहा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय चिकित्सा संघ (आइएमए) ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री ने लोगों को कोविड-19 के संक्रमण को थामने में जुटे स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति आभार जताने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने थाली-ताली बजाकर चिकित्सा, बिजली-पानी जैसी अनिवार्य सेवाओं में जुटे कर्मयोगियों के प्रति अभार जताने की अपील की थी।

पत्र में कहा गया है, 'अपने सभी सदस्यों की ओर से भारतीय चिकित्सा संघ लोगों को सामूहिक रूप से देश भर के डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारियों के प्रति आभार जताने के लिए प्रेरित करने के आपके प्रयास की सराहना करता है। ये सभी बीमारी की रोकथाम में अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए अथक रूप से जुटे हैं। हम वादा करते हैं कि सरकार के साथ जीवन की इस लड़ाई में राष्ट्र को पराजित नहीं होने देंगे। हम हर समय आपके साथ हैं।'

कचरा निस्तारण में एहतियात बरतें आइसोलेशन वार्ड : सीपीसीबी

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सभी स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों को निर्देश दिया है कि वे आइसोलेशन वार्डों से निकलने वाले कचरे के निस्तारण में एहतियात बरतें। बोर्ड ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी की हैं।

सीपीसीबी ने देशभर के सभी स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों को निर्देश दिया है कि आइसोलेशन वार्डों में अलग रंग के कूड़ेदान रखे जाने चाहिए ताकि बायो-मेडिकल कचरा (बीएमडब्ल्यू) प्रबंधन नियमों-2016 और सीपीसीबी नियमों के मुताबिक कचरे को समुचित तरीके से अलग किया जा सके। सीपीसीबी का कहना है कि क्वारंटाइन सेंटरों या कैंपों से निकलने वाले बायोमेडिकल कचरे को पीले रंग के बैगों में अलग से एकत्रित किया जाना चाहिए। एहतियात के तौर पर कोविड-19 आइसोलेशन वार्डों से निकले कचरे को दो परतों वाले पीले बैगों (दो बैगों का इस्तेमाल करते हुए) में एकत्रित किया जाना चाहिए ताकि उनसे किसी तरह की लीकेज न हो।

कहा, अलग रंग के कूड़ेदान और पीले रंग के बैगों का करें इस्तेमाल

इसके अलावा कोविड-19 वार्डों से निकले कचरे को जिन बैगों में एकत्रित किया जाए, उन पर 'कोविड-19 कचरा' का लेबल लगाया जाए। इससे कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसिलिटी को इसकी पहचान करने में मदद मिलेगी। साथ ही कचरे को वहां पहुंचते ही प्राथमिकता के आधार पर आसानी से निस्तारित किया जा सकेगा। सीपीसीबी ने कोविड-19 आइसोलेशन वार्डों में कचरे के लिए अलग ट्रॉलियों का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा है और उन भी 'कोविड-19 कचरा' का लेबल लगाने के लिए कहा है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण निकायों को उनके राज्यों के कोविड-19 वार्डों, क्वारंटाइन केंद्रों और गृहों का रिकॉर्ड रखने और बायोमेडिकल वेस्ट नियमों के मुताबिक उनका समुचित एकत्रीकरण और निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

केंद्र सरकार ने सभी विभागों से कहा, न्यूनतम कर्मियों के साथ करें काम

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों को एक आदेश जारी कर न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार अपने सभी विभागों के कर्मचारियों को पहले ही घर से काम करने की अनुमति दे चुकी है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया है, 'घर से काम कर रहे अधिकारियों को हर समय टेलीफोन और संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहना चाहिए। किसी आवश्यक कार्य के लिए अगर उन्हें बुलाया जाए तभी कार्यालय आना चाहिए।' इसके मुताबिक, विभागाध्यक्ष आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल करते हुए एक रोस्टर बना सकते हैं जिनमें सलाहकार, अनुबंधित और आउटसोर्स कर्मचारी भी शामिल होंगे। सिर्फ ऐसे कर्मचारियों को 23 मार्च से 31 मार्च तक कार्यालय आने के लिए भी कहा जा सकता है।

खोले राज

अमेरिकी अखबार में पुरस्कार प्राप्त लेखक युद्धजीत भट्टाचार्य ने अपने चौथे लेख में बताया है कि जैश-ए-मुहम्मद का सरगना मसूद अजहर किस तरह से भारत में आतंकी हमले करवाता है

आतंकी संगठन हैं भारत-पाक के संबंधों की बाधा

वाशिंगटन, एएनआइ : जैश-ए-मुहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की गतिविधियां जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी रणनीति का हिस्सा हैं। यही संगठन कश्मीर समस्या के शांतिपूर्ण समाधान की राह के सबसे बड़ी बाधा भी हैं। यह बात एक भारतीय मूल के अमेरिकी विशेषज्ञ ने न्यूयॉर्क टाइम्स के अपने लेख में कही है।

अमेरिकी अखबार में पुरस्कार प्राप्त लेखक युद्धजीत भट्टाचार्य ने अपने चौथे लेख में बताया है कि जैश-ए-मुहम्मद का सरगना मसूद अजहर किस तरह से भारत में आतंकी हमले करवाता है। सन 1999 में अपहृत विमान को छोड़ने के बदले रिहा हुआ अजहर ये कृत्य पिछले करीब दो दशकों से कर रहा है। उसके संगठन के हाल के वर्षों में हुए हमलों से भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और वहां गुस्सा पैदा हुआ है। ऐसे ही एक हमले में फरवरी 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया गया था जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इसी के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के अड्डे को निशाना बनाया था। इसी के

आतंकी गतिविधियां हैं जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी रणनीति का हिस्सा

अमेरिकी अखबार में भारतीय विशेषज्ञ लेखक ने लिखा

प्रतीकात्मक।

बाद बढ़े तनाव से भारत और पाकिस्तान युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे। इस लिहाज से जैश और उस जैसे अन्य आतंकी संगठन भारत और पाकिस्तान के शांतिपूर्ण संबंधों की राह में सबसे बड़ी बाधा हैं।

भविष्य में जैश या उस जैसे किसी संगठन का भारत में हमला परमाणु हथियार संपन्न भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का कारण बन सकता है। मसूद अजहर का पाकिस्तान में स्वतंत्रता से काम करना और आजाद घूमना भारतीय सैन्य अधिकारियों के गुस्से की बड़ी वजह है। वैश्विक आतंकी घोषित होने के बावजूद वह पाकिस्तान में छिपकर रह रहा है और अपने संगठन को सक्रिय किए हुए है। पाकिस्तान उसे या उसके संगठन के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है। भारत और वैश्विक समुदाय की कार्रवाई की मांग पर वह अजहर के खिलाफ सुबूत की मांग करता है। जबकि वास्तविकता यह है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ जैश ए मुहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों का भारत से छद्म युद्ध में दशकों से इस्तेमाल कर रही है। भारत के जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से पाकिस्तान की रणनीति को बड़ा झटका लगा है। वह इसीलिए इस मुद्दे को जोर-शोर से वैश्विक मंचों पर उठा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में अवकाश बढ़ाने पर आज हो सकता है फैसला

नई दिल्ली, आइएएनएस : कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की सोमवार को बैठक होगी, जिसमें अवकाश को दो हफ्ते से बढ़ाकर चार हफ्ते करने के सुझावों पर विचार किया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) ने अवकाश को बढ़ाने का सुझाव दिया है। शीर्ष अदालत में अवकाश 23 मार्च से शुरू हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन वीडियो कांफ्रेंसिंग के विकल्प का भी परीक्षण कर रहा है, जिसमें वकील एक कमरे से जिरह कर सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे से एससीबीए ने 21 मार्च को छुट्टियां बढ़ाने का अनुरोध किया था। एससीएओआरए के सचिव जोसेफ अरिस्टोटल ने कहा कि अभी छुट्टियां बढ़ाई जाती है तो गर्मी की छुट्टियां कम की जा सकती हैं और शनिवार को भी काम किया जा सकता है।

कह के रहेंगे माधव जोशी